International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Vol. 1 No.1
Sept – Oct2013

HINDI

वैश्विक परिप्रेक्ष में उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ

डॉ. श्रीकांत बी. संगम
सह प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, सी.एस.बी. कला, एस.एम.आर.पी. विज्ञान और
जी.एल.आर. वाणिज्य स्नातक महाविद्यालय, रामदुर्ग-591123
Email: sbshindi@gmail.com

शिक्षा किसी भी आधुनिक, समय, उन्नत और विकसित कहे जाने वाले समाज का अनिवार्य लक्षण है। इसके अभाव में बहु आयामी प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती। एक शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित समाज व शिक्षित राष्ट्र ही प्रगति के मार्ग पर अनवरत यात्रा कर पाने में समर्थ हो सकता है। शिक्षा एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया है। जिसका क्षेत्र असीमित है, इसलिए उसके उद्देश्य भी सीमित नहीं हो सकते। उनमें विविधता का होना अनिवार्य है। शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए उसके उद्देश्यों का निर्धारण परम आवश्यक है।

मानव की आत्मा को परिष्कृत करके उसे आत्म साक्षात्कार कराने जैसे शिक्षा के परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत में शिक्षा का उदय उस समय में हुआ जब आज के सर्वाधिक समय, संस्कृत और विकसित कहे जाने वाले राष्ट्र असभ्यता के अंधकार में अपना जीवन मार्ग ढूँढ रहे थे। उपनिषदों में कहा गया है- 'विद्या वह है जिसके द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है।' इससे मिलता जुलता कथन यह भी है कि 'विद्या वह है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है।' प्लेटो भी मानते हैं कि 'शिक्षा बालक के शरीर और आत्मा में सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है जिसके वह योग्य है" अरस्तू भी कहा है 'स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण को शिक्षा कहते हैं।' समग्रतः शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना उसे सच्चरित्र, सुयोग्य नागरिक बनाना एवं सम्पूर्ण मानव बनाना है।

आज प्रत्येक राष्ट्र में उच्च शिक्षा को विशेष महत्व दिया जा रहा है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, विद्वान, साहित्यकार, नेता, कवि, दार्शनिक, लेखक-आलोचक उच्च शिक्षा के प्रांगण से ही उत्पन्न होते हैं। उच्चकोटि के सत्यान्वेषण के लिए विश्वविद्यालय ही एक ऐसी प्रयोगशाला है जो ज्ञान के क्षेत्र को विस्तृत बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकते हैं। सम्पूर्ण विश्व की भाँति भारत में भी प्राथमिक शिक्षा को आधारशिला के रूप में तथा उच्चशिक्षा को मुकुट के रूप में स्वीकार किया गया है। जहाँ तक भारत में उच्चशिक्षा की व्यवस्था एवं विकास का प्रश्न है तो इसे सामान्यतः वैदिक, बौद्ध, मुस्लिम, ब्रिटिश तथा स्वतंत्रता के उपरांत के कालक्रम में विभाजित कर विवेचित किया जा सकता है।

स्वतंत्रता के उपरांत भारत में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा से लेकर व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं और शिक्षा का क्षेत्र न केवल विस्तृत हुआ अपितु बहुआयामी भी हो गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद से ही भारत में शिक्षा संबंधी नीतियों, शिक्षा की संरचना, शिक्षण पद्धतियों आदि सभी क्षेत्रों में सुधार एवं विकास के लिए अनेक सार्थक प्रयास किए जाते रहे हैं। शैक्षिक असमानताएँ एवं शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाएँ भी निर्धारित की गई हैं।

भारतीय उच्च प्रणाली पर दृष्टिपात करने से उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों के प्रथम स्पर्श को स्पष्टतः अनुभव किया जा सकता है। बात वर्तमान परीक्षा-प्रणाली की हो या स्नातक स्तर की शिक्षा की या फिर

विश्वविद्यालय स्तर की योजनाओं की ब्रिटिश शिक्षा का प्रभाव सभी पर स्पष्ट लक्षित होता है। आई.आई.टी. के सभी पैटर्न यू.एस. के तकनीकी संस्थानों के पैटर्न पर आधारित हैं। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त अध्ययन केन्द्र (IGNOU) यू.के. के ओपन युनिवर्सिटी की अवधारणा पर आधारित है।

भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 50 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। इससे विदेशी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के लिए भारत में सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी में अपने परिसर खोलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस निर्णय के पीछे सरकार की दलील है कि भारत से प्रतिवर्ष लगभग एक लाख तीस हजार छात्र-छात्राएँ उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं और वहाँ के विश्वविद्यालों में प्रवेश लेते हैं और वर्तमान में विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्र-छात्राओं को लगभग चार अरब डॉलर प्रतिवर्ष खर्च करने होते हैं, भारत में उन विश्वविद्यालयों के परिसर स्थापित होने से भारत से विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में भी कमी आएगी।

यह सत्य है कि सूचना प्रौद्योगिकी 21वीं सदी में भूमण्डलीकरण का एक महान् अवदान है। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कम्प्यूटिंग, टेलिकम्यूनिकेशन और माइक्रोइलैक्ट्रानिकी ने भारत में उच्च शिक्षा के सांस्थान में आधुनिक अध्ययन-अध्यापन एवं शोध के क्षेत्र में विशेष सहायक तत्व रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के अभाव में भारतीय उच्च शिक्षा काफी पीछे रह जाती है। अध्यापक एवं विद्यार्थि शिक्षण की पारंपरिक चार दीवारी से बाहर निकलकर, भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण कर एक नवीनतम साइबर संसार के माध्यम से शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने तार्किकता, वैचारिक योग्यता, निर्णयात्मक क्षमता, आत्म-विश्लेषण, मूल्यपरक तार्किक एवं वैज्ञानिक शिक्षा के माध्यम से भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में नूतन ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित की है।

विदेशी विश्वविद्यालयों का आना भारतीय शिक्षा की स्थिति को और भी अधिक खराब ही करेगा क्योंकि विदेशी विश्वविद्यालय जो कि मात्र लाभ कमाने एवं भारत में स्थायी रूप से स्थापित होने के उद्देश्य से आने के प्रयास में हैं। भारतीय शिक्षण संस्थानों के अनुभवी एवं सुयोग्य अध्यापकों को अत्यधिक वेतनमान का लोभ देकर अपनी ओर खींच ले जाएंगे और भारतीय विश्वविद्यालय कानून के स्तर पर भी इनका मुकाबला कर पाने में असमर्थ होंगे। परिणाम यह होगा कि भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों का स्तर इन अनुभवी व योग्य अध्यापकों के अभाव में और भी गिर जाएगा। सैद्धांतिक एवं उद्देश्यविहीन शिक्षा, बोझिल पाठ्यक्रम, अवैज्ञानिक एवं अविश्वसनीय परीक्षा प्रणाली, प्रत्येक स्तर पर संसाधनों की कमी जैसी अनेक समस्याएँ शिक्षाविदों, शिक्षकों, प्रशासकों, अभिभावकों व विद्यार्थियों के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी है। आयोग और समितियों के गठन मात्र से, योजनाएँ बनाकर फाइलों में बन्द कर देने से, शिक्षा के क्षेत्र में नाममात्र वित्तीय परिव्यय बढ़ा देने से इस क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। उच्च शिक्षा का विदेशीकरण ज्ञानार्जन, समाज सेवा और राष्ट्रनिर्माण के लिए खतरे की घण्टी है। अध्ययन-अध्यापन व शोध के क्षेत्र में भारतीय विश्वविद्यालयों का मुख्य लक्ष्य, पारंपरिक, अधुनातन एवं नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। भारतीय उच्च शिक्षा में गुरुकुल के वैदिक, नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती है ताकि हम अपनी सांस्कृतिक सम्पदा, अपने रीति-रिवाज अपनी आध्यात्मिकता को सुरक्षित रख सकें।

परंतु पिछले दो दशकों से विश्व बैंक के दबाव में उच्च शिक्षा के बजट में लगातार कटौती की जा रही है। परिणाम यह हुआ है कि कुछेक को छोड़कर अधिकांश विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक ढ़ांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के मलबे पर निजी शैक्षणिक संस्थानों के तीव्रतम विकास से जहाँ

उच्चशिक्षा को गुणवत्ता में गिरावट आ रही है वहीं निजीकरण की व्यवस्था अनुबंध प्रणाली का पर्याय बनती जा रही है।

भारतीय उच्च शिक्षा पर वैश्वीकरण का मिश्रित-सा प्रभाव प्रतीत होता है। वैश्विक परिदृश्य में प्रगतिशील राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धा की क्षमता अपेक्षाकृत कम है। वैश्वीकरण एक गंभीर मुद्दा है, और राष्ट्र निर्माण और सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में इस पर गंभीर विचार विमर्श अपेक्षित है। इस संदर्भ में व्याप्त बुराईयों और कठिनाईयों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर दीर्घकालीन नियोजन, प्रशासकीय एवं राजनीतिक दृढ़ संकल्प शक्ति, जन सहयोग व जन कल्याण की भावना से सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाहन करने से ही इस चुनौती का सामना किया जा सकता है।

वैश्वीकरण का अर्थ भ्रातृत्व, पारस्परिक समझ, सांस्कृतिक-सामाजिक समन्वय, संयम, सहनशीलता, परस्पर सम्मान की भावना से अनुप्राणित होना है। अतः इस दिशा में जल्दबाजी से नहीं बल्कि सहजता व सही सोच से कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। समुचित वातावरण के निर्माण से 'विश्वगाँव' की परिकल्पना साकार हो सकेगी और हम विश्वस्तरीय नागरिकों का निर्माण करने में सक्षम हो सकेंगे।

संदर्भ सूची :

1. भूमण्डलीकरण के उच्च शिक्षा : चुनौतियाँ एवं संदर्भ- डॉ. विनोद कालरा
2. वैश्वीकरण और उच्च शिक्षा : समस्याएँ एवं नूतन संभावनाएँ- डॉ. नीतू शर्मा
3. वैश्वीकरण का शिक्षा पर प्रभाव : दा इंडियन वायर
4. भारते में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण- पंकज पालेवाल
5. भारतीय उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ- दीनानाथ बत्रा
6. वैश्वीकरण के युग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सबसे बड़ी चुनौती- दरभंगा, 28 जुलाई, 2014
7. पंचशील शोध समीक्षा- सं. डॉ. हेतु भारद्वाज (2011)
8. समकालीन भारतीय साहित्य- साहित्य अकादेमी की द्वैमासिक पत्रिका- जून-2015